



49

नोट्स

1

खबरें जोड़ी गईं

GS1 • 2

GS2 • 23

GS3 • 24

पेपर मिश्रण

विषय सूची

सभी नोट्स, पेपर के अनुसार

GS1 इतिहास • समाज • भूगोल 2 नोट्स

इतिहास एवं संस्कृति 1

भूगोल 1

GS2 राजव्यवस्था • शासन • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध 23 नोट्स

राजव्यवस्था एवं संविधान 4

शासन 3

सामाजिक न्याय 9

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 7

GS3 अर्थव्यवस्था • विज्ञान-तकनीक • पर्यावरण • सुरक्षा 24 नोट्स

अर्थव्यवस्था 9

कृषि 2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 3

आंतरिक सुरक्षा 5

हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के साथ मेन्स प्रश्न। एक ही खबर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के सार में सबसे ज़रूरी खबरें और अभ्यास प्रश्न हैं।

इतिहास एवं संस्कृति

1

ANCIENT & MEDIEVAL INDIA

P

9 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/99429

प्राचीन तेलुगु शिलालेख से 11वीं सदी में मंदिर के लिए भूमि दान का खुलासा

चर्चा में क्यों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 11वीं शताब्दी के एक तेलुगु शिलालेख को पढ़ा है, जिसमें मंदिर की पूजा के लिए भूमि दान का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह शिलालेख मध्यकालीन भूमि स्वामित्व और धार्मिक प्रथाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

संस्था	ASI (Archaeological Survey of India) पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।
स्थान	यह शिलालेख आंध्र प्रदेश के येरगोडपलेम मंडल में पाया गया था।
तथ्य	यह शिलालेख 11वीं शताब्दी सी.ई. का है।

मेन्स प्रश्न मध्यकालीन भारत के सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक इतिहास को समझने में पुरालेखीय साक्ष्यों के योगदान पर चर्चा कीजिए।

भूगोल

1

GEOPHYSICAL PHENOMENA (EARTHQUAKES, CYCLONES, VOLCANOES)

P

9 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/99686

आंध्र प्रदेश में अगस्त में 56% बारिश की कमी: नायडू ने दिए वॉटर मैनेजमेंट के निर्देश

चर्चा में क्यों एल नीनो के कारण आंध्र प्रदेश में वर्षा की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने आपातकालीन जल प्रबंधन उपायों को लागू करने की पहल की है।

तथ्य	El Niño के कारण अगस्त के लिए आंध्र प्रदेश में वर्षा की कमी 56% अनुमानित है।
तथ्य	वर्तमान जलाशय भंडारण: 563.05 TMC ft (पिछले वर्ष के 825.67 TMC ft की तुलना में)।
योजना	जलधारा योजना: आंध्र प्रदेश में ₹3,409.35 करोड़ की लागत वाली जल प्रबंधन परियोजना।

मेन्स प्रश्न भारत में जल सुरक्षा पर अल नीनो (El Niño) जैसी जलवायु घटनाओं के प्रभाव की चर्चा कीजिए और सूखा-प्रवण राज्यों में सतत जल प्रबंधन हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

राज्यवस्था एवं संविधान

4

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99967

6 अगस्त को चीफ जस्टिस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की कॉलेजियम ने चार न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति और दो न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है, जो न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को रेखांकित करती है।

संस्था	कॉलेजियम प्रणाली वह तंत्र है जिसका उपयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।
पद	वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के प्रमुख हैं।
तथ्य	कॉलेजियम ने पटना, कलकत्ता, बॉम्बे और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के उन्नयन की सिफारिश की है।

मेन्स प्रश्न न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में कॉलेजियम प्रणाली के महत्व पर चर्चा कीजिए, साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता से संबंधित चिंताओं का विश्लेषण कीजिए।

STATUTORY, REGULATORY & QUASI-JUDICIAL BODIES

P

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99835

तमिलनाडु ने Justice D. Krishnakumar को नया State Law Commission Chairman नियुक्त किया

चर्चा में क्यों तमिलनाडु सरकार ने कानूनी सुधारों की निगरानी के लिए राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन किया और न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया।

संस्था	राज्य विधि आयोग (State Law Commission): एक सांविधिक निकाय (statutory body) जिसका कार्य कानूनी सुधारों की जांच करना और राज्य के कानूनी ढांचे में सुधार के सुझाव देना है।
पद	न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार: मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
तथ्य	तमिलनाडु राज्य विधि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

मेन्स प्रश्न राज्य स्तर पर कानूनी सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन और विधि के शासन को बनाए रखने में राज्य विधि आयोगों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99658

वक्फ फीस छूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें इस विषय पर विचार किया जाना है कि क्या वक्फ संस्थानों को राज्य वक्फ न्यायाधिकरण (State Waqf Tribunal) के समक्ष न्यायालय शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

संस्था	राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल: वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय।
अधिनिर्णय	Waqf Act: भारत में वक्फ संस्थानों के प्रबंधन और संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
तथ्य	गुजरात उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में निर्णय दिया कि Waqf संस्थान न्यायालय शुल्क (court fees) से मुक्त नहीं हैं।

मेन्स प्रश्न धार्मिक बंदियों के प्रशासन में न्यायिक निरीक्षण के महत्व और संस्थागत विशेषाधिकारों तथा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

ELECTIONS, ECI & ELECTORAL REFORMS

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99607

Voter Mismatch: बेंगलुरु अर्बन में ASDDO लिस्ट 2024 के वोटों से मैच

चर्चा में क्यों बेंगलुरु अर्बन की मतदाता सूची में डेटा विसंगति यह दर्शाती है कि 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट, मृत और अन्य' (ASDDO) श्रेणी में वर्गीकृत मतदाताओं की संख्या 2024 के लोकसभा चुनावों में डाले गए मतों की संख्या से अधिक है।

तथ्य	ASDDO: मतदाता सूची संशोधन में एक श्रेणी जिसमें अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), डुप्लिकेट (Duplicate), मृत (Dead) और अन्य (Others) शामिल हैं।
संस्था	निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
तथ्य	यह विसंगति Special Intensive Revision (SIR) डेटा में पहचानी गई थी।

मेन्स प्रश्न भारत में चुनावी प्रक्रिया की शुचित्ता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर और सटीक संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

कैबिनेट पैनल ने राहुल नवीन का ED कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया

चर्चा में क्यों कैबिनेट की नियुक्तियों की समिति ने राहुल नवीन के सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है।

संस्था	Enforcement Directorate (ED): वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी जो धन शोधन (money laundering) और अन्य वित्तीय अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।
पद	कैबिनेट की नियुक्तियां समिति (Appointments Committee of the Cabinet - ACC): एक उच्च-स्तरीय समिति जो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यकाल की सिफारिश करती है।
तथ्य	राहुल नवीन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के सदस्य हैं और अगस्त 2024 से ED का नेतृत्व कर रहे हैं।

मेन्स प्रश्न वित्तीय अखंडता बनाए रखने में प्रवर्तन निदेशालय के महत्व और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने में कैबिनेट की नियुक्ति समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की वास्तविक समय में डिजिटल निगरानीप्रदान करने हेतु 'जल सारथी' ऐप लॉन्च किया है

चर्चा में क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की वास्तविक समय में डिजिटल निगरानीप्रदान करने हेतु 'जल सारथी' ऐप लॉन्च किया है।

संस्था	Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) इस ऐप के विकास के लिए जिम्मेदार निकाय है।
तथ्य	लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के भीतर इस ऐप ने 1.2 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए।
विज्ञान	यह ऐप पेयजल योजनाओं की वास्तविक समय (real-time) की निगरानी के लिए भू-टैग (geo-tagged) संपत्तियों का उपयोग करता है।

मेन्स प्रश्न जल सारथी जैसे ई-गवर्नेंस उपकरण ग्रामीण भारत में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

RERA-K का प्लान: नियमों के उल्लंघन पर 2 हफ्ते में बिल्डर्स की संपत्ति नीलाम होगी

चर्चा में क्यों RERA-K ने राजस्व वसूली में सुधार हेतु गैर-अनुपालन करने वाले बिल्डरों की संपत्तियों की नीलामी के लिए RERA अधिनियम, 2016 की धारा 40(2) को कार्यान्वित करने हेतु एक परिपत्र जारी किया है।

अधिनियम	RERA Act, 2016: रियल एस्टेट परियोजनाओं को विनियमित करने और गृह-खरीदारों के हितों की रक्षा करने वाला प्राथमिक विधान।
संस्था	RERA: रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय।
तथ्य	नए प्रवर्तन उपायों से पूर्व केवल 10% Revenue Recovery Certificates की वसूली की गई थी।
तथ्य	बिल्डरों को नीलामी से पहले अनुपालन सत्यापित करने और संपत्ति का खुलासा करने के लिए दो सप्ताह की अवधि दी जाती है।

मेन्स प्रश्न भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में 'रेरा' (RERA) अधिनियम के प्रवर्तन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

VULNERABLE SECTIONS (SC/ST, MINORITIES, DISABLED, ELDERLY, CHILDREN)

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/100259

लद्दाख में जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से शुरू

चर्चा में क्यों 17 अगस्त से शुरू होने वाले लद्दाख के जनगणना के दूसरे चरण में भारत में जाति गणना के लिए पहली बार एक 'ओपन-एंडेड' (खुला) कॉलम शामिल किया गया है।

- तथ्य** लद्दाख में जनगणना में 40 विभिन्न मापदंडों (parameters) पर प्रश्न शामिल हैं।
- तथ्य** जाति गणना के लिए पूर्व-परीक्षण (pre-test) 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था।
- तथ्य** स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है जब भारत अपनी जनगणना में जाति का विवरण दर्ज करेगा।

मेन्स प्रश्न भारत में समावेशी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जनगणना में जातिगत गणना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

VULNERABLE SECTIONS (SC/ST, MINORITIES, DISABLED, ELDERLY, CHILDREN)

P

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/100268

बहादुरी, खेल, कला: PMRBP-2026 के लिए नामांकन 15 अगस्त तक बढ़ाए गए

चर्चा में क्यों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)-2026 के लिए नामांकन की समय-सीमा को व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

- योजना** PMRBP: विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों द्वारा की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- तथ्य** पात्रता: 31 जुलाई, 2026 तक 5 से 18 वर्ष की आयु के भारतीय बच्चे।
- संस्था** National Awards Portal: राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

मेन्स प्रश्न भारत में जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की उपलब्धियों को मान्यता देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

VULNERABLE SECTIONS (SC/ST, MINORITIES, DISABLED, ELDERLY, CHILDREN)

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/100124

केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एसिड हमले के मामलों में दोषियों पर लगाए गए जुर्माने से

चर्चा में क्यों केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एसिड हमले के मामलों में दोषियों पर लगाए गए जुर्माने से स्वतंत्र और अतिरिक्त रूप से 'पीड़ित मुआवजा योजना' के तहत मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

- संस्था** District Legal Services Authority (DLSA) जिला स्तर पर कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवजे प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्य** न्यायालय ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए दीर्घकालिक चिकित्सा आवश्यकताओं और पुनर्वास लागत के लिए मुआवजे पर जोर दिया।

मेन्स प्रश्न भारत में लैंगिक आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में स्वतंत्र पीड़ित मुआवजा योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।

HEALTH POLICY & PUBLIC HEALTH

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/100102

7 साल बाद नेशनल रजिस्ट्री से भारत के दो-तिहाई नर्स गायब

चर्चा में क्यों सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत के नर्सिंग कार्यबल का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा अभी भी 'Nurses Registration and Tracking System' (NRTS) पर पंजीकृत नहीं है, जो स्वास्थ्य सेवा कार्यबल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता है।

- संस्था** NRTS: Nurses Registration and Tracking System नर्सिंग कर्मियों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच है।
- तथ्य** वर्तमान में 46.02 लाख नर्सिंग कर्मियों में से केवल 14.24 लाख ही NRTS पर पंजीकृत हैं।
- पद** नर्सिंग कर्मियों का पंजीकरण भारत के स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है।

मेन्स प्रश्न भारत में स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के औपचारिकरण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणालियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु को 26 जुलाई तक ट्रांसजेंडर रहैब स्कीम बनाने के निर्देश दिए

चर्चा में क्यों मद्रास उच्च न्यायालय ने सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुक-स्तरीय पुनर्वास योजना बनाने हेतु तमिलनाडु सरकार को निर्देशित किया है।

संस्था	मद्रास उच्च न्यायालय: भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी।
तथ्य	न्यायालय ने स्थानीय पुनर्वास के लिए योजना को 'taluk' स्तर पर लागू करने का निर्देश दिया।
पद	मुख्य सचिव: राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पदस्थ सिविल सेवक, जो कार्यकारी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक समावेश सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनके प्रभावी पुनर्वास हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

NEET UG 2026 के प्रश्नों वाली एक लीक हुई PDF फाइल के मिलने के बाद, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

चर्चा में क्यों NEET UG 2026 के प्रश्नों वाली एक लीक हुई PDF फाइल के मिलने के बाद, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने CBI जांच सौंपी है, जिससे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं की शुचिता पर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

संस्था	NTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET UG आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
संस्था	CBI: Central Bureau of Investigation भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है।
तथ्य	NEET UG 2026 का आयोजन 13 विभिन्न भाषाओं में किया गया था।

मेन्स प्रश्न भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रश्नपत्रों के रिसाव (पेपर लीक) को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

तमिलनाडु में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से ग्रामीण महिलाओं की वर्कफोर्स बढ़ाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों तमिलनाडु सरकार ने प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और भूमि स्वामित्व प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और पोषण को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है।

संस्था	M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है।
तथ्य	यह पहल प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और Millets के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और पोषण को लक्षित करती है।
पद	P. Venkataramanan तमिलनाडु में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में सतत कृषि विकास की प्राप्ति में ग्रामीण महिलाओं को भूमि स्वामित्व और पोषण सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 'गोल्डन ऑवर' के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार हेतु 108 एम्बुलेंस में एंटी-स्नेक वेनम (ASV) को शामिल करने की घोषणा की है

चर्चा में क्यों आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 'गोल्डन ऑवर' के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार हेतु 108 एम्बुलेंस में एंटी-स्नेक वेनम (ASV) को शामिल करने की घोषणा की है।

तथ्य	जून 2025 से अब तक आंध्र प्रदेश में 3,104 आपातकालीन सांप के काटने (snakebite) की कॉल प्राप्त हुई हैं।
स्थान	इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर (Emergency Response Centre) आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में स्थित है।
विज्ञान	ASV (Anti-Snake Venom) विषप्रहार (envenomation) के लिए प्राथमिक उपचार है।

मेन्स प्रश्न आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में 'गोल्डन ऑवर' (स्वर्ण घंटे) के महत्व पर चर्चा कीजिए और भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

तेलंगाना सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के संघों के साथ उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मांगों के समाधान हेतु वार्ता की

चर्चा में क्यों तेलंगाना सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के संघों के साथ उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मांगों के समाधान हेतु वार्ता की, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया।

तथ्य	Gig workers वे व्यक्ति हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे कि डिलीवरी, राइड-हेलिंग) के माध्यम से मध्यस्थता वाले कार्य करते हैं।
संस्था	तेलंगाना गिग वर्कर्स वेल्फेयर एक्ट (Telangana Gig Workers Welfare Act) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राज्य-स्तरीय विधायी पहल है।

मेन्स प्रश्न भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और इन मुद्दों के समाधान में राज्य-आधारित विधायी ढाँचों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

7

यू.एस. उपराष्ट्रपति J.D. Vance ने भारत-U.एस. रिश्तों को मजबूत करने के लिए PM Modi को फोन किया

चर्चा में क्यों अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के विषय पर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया।

पद	J.D. Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
तथ्य	सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियां और महत्वपूर्ण खनिज।
तथ्य	संदर्भगत कारक: तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक रक्षा समझौता।

मेन्स प्रश्न बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

तुर्की FM: नया मक्का समझौता NATO के Article 5 जैसा, आक्रामकता को रोकने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' की घोषणा की है, जो NATO के अनुच्छेद 5 पर आधारित है।

अंत.	संगठन	NATO Article 5: सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।
तथ्य		Mecca Joint Defence Agreement लगभग 32 महीनों (दो वर्ष और आठ महीने) तक विकास के अधीन था।
स्थान		सऊदी अरब: इस गठबंधन के सामान्य सचिवालय (General Secretariat) की मेजबान देश।

मेन्स प्रश्न मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में उभरते क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा समझौतों के मौजूदा वैश्विक सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

कोच्चि में Indian Navy और U.S. Navy ने 5 दिनों का विस्फोटक निरोधक अभ्यास शुरू किया

चर्चा में क्यों समुद्री अंतर-संचालनीयता (interoperability) को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय और अमेरिकी नौसेनाएं कोच्चि में एक विशेष विस्फोटक आयुध निपटान (explosive ordnance disposal) अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित कर रही हैं।

तथ्य	यह इस विशिष्ट द्विपक्षीय प्रशिक्षण का 8वां संस्करण है।
स्थान	यह अभ्यास केरल के कोच्चि में स्थित Southern Naval Command में आयोजित किया जा रहा है।
तथ्य	अभ्यास की अवधि पांच दिन (10-14 अगस्त, 2026) है।

मेन्स प्रश्न एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।

रूस ने Strait of Hormuz के जोखिम से बचने के लिए ईरान के रास्ते रेल लिंक का प्रस्ताव दिया

चर्चा में क्यों रूस के उप-प्रधानमंत्रीमरात खुसनुलिन ने 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' में समुद्री जोखिमों से बचने के लिए एक बहु-देशीय रेल कॉरिडोर (रूस-तुर्कमेनिस्तान-ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) का प्रस्ताव दिया है।

स्थान	हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
स्थान	बोस्फोरस: एक तुर्की जलडमरूमध्य जो काला सागर (Black Sea) को मारमारा सागर (Sea of Marmara) से जोड़ता है।
विज्ञान	IRGC: इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है।
तथ्य	प्रस्तावित रेल लिंक में पांच देश शामिल हैं: Russia, Turkmenistan, Iran, Afghanistan और Pakistan।

मेन्स प्रश्न समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) में भू-राजनीतिक तनावों के बीच व्यापार मार्गों के विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहु-पक्षीय परिवहन गलियारों (multi-modal transport corridors) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

Canada ने 2026 के पहले हिस्से में 3,323 भारतीयों को निकाला, बनाया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों वर्ष 2026 की प्रथम छमाही में कनाडा द्वारा रिकॉर्ड 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया, जो द्विपक्षीय आप्रवासन प्रवर्तन और नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है।

तथ्य	H1 2026 में कनाडा द्वारा 3,323 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया।
तथ्य	कनाडा में निर्वासन (deportation) के लिए भारतीयों ने मेक्सिकियों को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी राष्ट्रीयता का स्थान प्राप्त कर लिया है।
तथ्य	निर्वासन आदेशों को गैर-अनुपालन, वीजा ओवरस्टे और धोखाधड़ी के आधार पर लागू किया जाता है।

मेन्स प्रश्न भारत और पश्चिमी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और प्रवासी अनुभव पर कड़े आप्रवासन नीतियों के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

भारत-जापान पैनल ने टेक और ट्रेड के जरिए मेजर पावर्स को टक्कर देने के लिए "G-Minus-Two" पर नजर डाली

चर्चा में क्यों IJCCI और मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में भारत-जापान संबंधों को तकनीकी और व्यापारिक क्षेत्रों में सुदृढ़ करने हेतु 'G-Minus-Two' अवधारणा पर प्रकाश डाला गया, जिसका उद्देश्य प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना है।

संस्था	IJCCI: Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry।
विज्ञान	भारत-जापान तकनीकी सहयोग के लिए Semiconductors और AI को मुख्य स्तंभों के रूप में पहचाना गया है।
तथ्य	'G-Minus-Two' अवधारणा भारत और जापान के बीच एक रणनीतिक आर्थिक और तकनीकी संरेखण (alignment) को संदर्भित करती है।

मेन्स प्रश्न भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी के माध्यम *midst* में भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने और तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रमुख शक्तियों के प्रभाव का मुकाबला करने में निहित महत्व पर चर्चा कीजिए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गोदावरी-कावेरी-गुंडार नदी जोड़ो परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा देने का अनुरोध किया है और श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है

चर्चा में क्यों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गोदावरी-कावेरी-गुंडार नदी जोड़ो परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्जा देने का अनुरोध किया है और श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

संस्था	NWDA: National Water Development Agency भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं (river linking projects) के लिए नोडल एजेंसी है।
स्थान	गोदावरी, कावेरी और गुंडार दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं।
तथ्य	रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है।

मेन्स प्रश्न भारत में जल की कमी को दूर करने में नदी जोड़ो परियोजनाओं के महत्व और अंतर-राज्यीय एवं अंतराष्ट्रीय जल साझाकरण से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

अर्थव्यवस्था

9

MONETARY POLICY, RBI & BANKING

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99818

भारत सरकार की सफाई: UPI पर पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजेक्शन रहेंगे फ्री

चर्चा में क्यों भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति-से-व्यक्ति (person-to-person) UPI लेनदेन निःशुल्क रहेंगे।

संस्था	NPCI (National Payments Corporation of India) वह संस्था है जो UPI संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
अधिनियम	Payment and Settlement Systems Act, 2007 भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान है।
तथ्य	MDR (Merchant Discount Rate) वह शुल्क है जो एक व्यापारी द्वारा लेनदेन की प्रक्रिया के लिए बैंक या पेमेंट प्रोसेसर को भुगतान करता है।

मेन्स प्रश्न वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के महत्व और इसकी दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

GROWTH, INFLATION & MACRO INDICATORS

P

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99816

EEMAGINE में इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट समित गर्ग

चर्चा में क्यों इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (EEMA) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2030 तक भारत के मनोरंजन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है, साथ ही नियामक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

तथ्य	भारतीय मनोरंजन क्षेत्र का वर्तमान मूल्यांकन: \$32.2 बिलियन।
तथ्य	2030 तक भारतीय मनोरंजन क्षेत्र का अनुमानित मूल्यांकन: \$59.2 बिलियन।
तथ्य	क्षेत्र के लिए अनुमानित वार्षिक विकास दर: 16% से 26%।
संस्था	EEMA: Events and Entertainment Management Association।

मेन्स प्रश्न भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में घटना और मनोरंजन उद्योग (Events and Entertainment Industry) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और इस क्षेत्र की विनियामक बाधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।

INDUSTRY, INVESTMENT & MSMEs

P

M

9 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/99795

2019 से 2,279 नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में J&K के लोगों की 90% हिस्सेदारी, 75,848 नौकरियां पैदा

चर्चा में क्यों एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में NCSS-2021 के अंतर्गत 2019 से जम्मू और कश्मीर में स्थानीय उद्यमिता और औद्योगिक विकास की सफलता पर प्रकाश डाला गया है।

संस्था	गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति: लोकसभा/राज्यसभा की एक समिति।
योजना	नई केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021 (NCSS-2021): औद्योगिक विकास के लिए एक केंद्रीय पहल।
तथ्य	J&K की कुल प्रजनन दर (TFR): 1.5 (राष्ट्रीय औसत से कम)।
तथ्य	2019 से अब तक J&K की औद्योगिक इकाइयों में ₹16,598.97 करोड़ का निवेश।

मेन्स प्रश्न जम्मू और कश्मीर में स्थानीय उद्यमिता और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना क्षेत्रीय आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों में किस प्रकार योगदान दे सकता है, चर्चा कीजिए।

FPIs ने भारतीय इक्विटी में Rs 20,200-Crore का निवेश किया, 4 महीने की भारी बिकवाली के बाद पलटा रुख

चर्चा में क्यों जुलाई माह में भारतीय इक्विटी बाजार में FPIs द्वारा 20,200 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश दर्ज किया गया, जो पिछले चार महीनों से जारी बिकवाली के रुझान में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

- तथ्य | जुलाई में FPIs ने भारतीय इक्विटी में ₹20,200 करोड़ का निवेश किया।
- तथ्य | FPIs ने 2026 में कुल 2.41 लाख करोड़ रुपये की निकासी की।
- तथ्य | जुलाई में FPIs ने सामान्य मार्ग (general route) के माध्यम से ऋण (debt) में ₹622 करोड़ का निवेश किया।
- तथ्य | FPI निवेश के प्रमुख क्षेत्र ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य सेवा (healthcare) शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न भारतीय पूंजी बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों और घरेलू आर्थिक स्थिरता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

बेंगलुरु के ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए कर्नाटक ने Urban Mobility Mission Committee बनाई

चर्चा में क्यों कर्नाटक सरकार ने सतत शहरी परिवहन के लिए एक बहु-हितधारक मंच (multi-stakeholder platform) स्थापित करने हेतु बेंगलुरु के लिए शहरी गतिशीलता मिशन समिति (UMMCB) का गठन किया है।

- संस्था | UMMCB: बेंगलुरु के यातायात मुद्दों के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक समिति।
- पद | प्रियंक खड्गे: कर्नाटक के वर्तमान गृह मंत्री और UMMCB के अध्यक्ष।
- तथ्य | समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव और शहरी गतिशीलता (urban mobility) विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न तेजी से विस्तार कर रहे भारतीय शहरों में शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) की चुनौतियों और सतत परिवहन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहु-हितधारक समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

सिंगरेनी कोलियर्स ने कर्नाटक में 199.13 sq.km गोल्ड और कॉपर एक्सप्लोरेशन डील साइन की

चर्चा में क्यों सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने देवदुर्गा ब्लॉक में स्वर्ण और तांबे के अन्वेषण हेतु कर्नाटक खान एवं भूविज्ञान विभाग के साथ एक समझौता किया है।

- स्थान | देवदुर्गा ब्लॉक कर्नाटक के रायचूर और यादगीर जिलों में स्थित है।
- तथ्य | अन्वेषण क्षेत्र कुल 199.13 sq.km. को कवर करता है।
- संस्था | SCCL (Singareni Collieries Company Limited) एक प्रमुख खनन कंपनी और तेलंगाना राज्य की एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम (Public Sector Undertaking) है।
- तथ्य | अन्वेषण समझौता पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

मेन्स प्रश्न भारत के खनिज अन्वेषण और औद्योगिक विकास को गति देने में खनिज नीलामी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

एक हफ्ते में भारत के Forex Reserves में \$10.512 बिलियन का उछाल

चर्चा में क्यों RBI ने रिपोर्ट दी है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो \$692.866 बिलियन तक पहुँच गया है। यह वृद्धि विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए FCNR(B) जैसी योजनाओं जैसे उपायों द्वारा संचालित हुई है।

- तथ्य | 31 जुलाई, 2026 तक भारत के कुल forex reserves \$692.866 बिलियन तक पहुँच गए।
- संस्था | RBI (Reserve Bank of India) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) के प्रबंधन वाली प्राथमिक संस्था है।
- योजना | FCNR(B) योजना का उपयोग अनिवासी भारतीयों (NRIs) से विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
- तथ्य | SDRs (Special Drawing Rights) भारत की IMF के साथ आरक्षित स्थिति (reserve position) का हिस्सा हैं।

मेन्स प्रश्न भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की महत्ता का व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और बाहरी झटकों के प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Startup India Seed Fund से बिना गारंटी के बैंक लोन मिलेगा

चर्चा में क्यों स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) बैंक ऋण प्रदान करने के एक तंत्र के रूप में रेखांकित किया गया है।

योजना	Startup India Seed Fund Scheme: यह स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग और मार्केट एंट्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
तथ्य	यह योजना प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है।
संस्था	Confederation of Indian Industries (CII): भारत में एक प्रमुख व्यापारिक संघ।

मेन्स प्रश्न भारत में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के लिए ऋण अंतराल को पाटने और एक उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

आंध्र प्रदेश टैरिफ-आधारित बिडिंग के जरिए खरीदेगा 1,600 MW कोयला पावर

चर्चा में क्यों ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंध्र प्रदेश 1,600 MW कोयला आधारित तापीय ऊर्जा की खरीद हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

तथ्य	आंध्र प्रदेश टैरिफ-आधारित बोली के माध्यम से 1,600 MW कोयला-आधारित तापीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
संस्था	Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission (APERC) बिजली टैरिफ और बिजली खरीद को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय है।
संस्था	Central Electricity Authority (CEA) बिजली आवश्यकताओं के लिए Resource Adequacy Plan प्रदान करती है।
तथ्य	राज्य का दीर्घकालिक लक्ष्य 2035-36 तक 5,588 MW की बिजली क्षमता जोड़ना है।

मेन्स प्रश्न दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और कोयला-आधारित बिजली खरीद के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों और आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

कृषि

2

तमिलनाडु बजट 2026-27 में बागवानी के लिए ₹38.17 करोड़ का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों तमिलनाडु सरकार ने बागवानी बुनियादी ढांचे और एक नए प्रसंस्करण निगम की स्थापना पर केंद्रित वर्ष 2026-27 के लिए एक संशोधित कृषि बजट का प्रस्ताव दिया है।

तथ्य	तमिलनाडु के 2026-27 के बजट में बागवानी (horticulture) पहलों के लिए ₹38.17 करोड़ का कुल आवंटन किया गया है।
संस्था	तमिलनाडु कोकोनट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन: कटाई के पश्चात के बुनियादी ढांचे और निर्यात को समर्थन देने के लिए एक नई संस्था।
स्थान	कृष्णागिरी और तिरुपुर: बागवानी क्लस्टर विकास के लिए लक्षित प्रमुख पश्चिमी जिले।
तथ्य	930 एकड़ में उच्च-मूल्य वाले फलों (ब्लूबेरी और रामबुटान) की खेती के लिए ₹1.87 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में बागवानी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में बुनियादी ढांचा विकास और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।

पार्लियामेंट पैनल ने कमी दूर करने और सप्लाई बेहतर करने के लिए परमानेंट फर्टिलाइजर कमांड की मांग की

चर्चा में क्यों रसायन एवं उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति ने आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और वितरण संबंधी अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक स्थायी संयुक्त उर्वरक कमांड की सिफारिश की है।

संस्था	रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति: रसायन और उर्वरक क्षेत्र की नीति और कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
अधिनियम	Fertilizer (Movement Control) Order, 1973: भारत में उर्वरकों के परिवहन और वितरण को नियंत्रित करने वाला विनियमन।
स्थान	हॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल और उर्वरक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
तथ्य	समिति ने अंतिम छोर तक वितरण (last-mile delivery) समन्वय के लिए एक 'स्थायी संयुक्त उर्वरक कमांड' (permanent joint fertilizer command) की सिफारिश की।

मेन्स प्रश्न भारत की उर्वरक वितरण प्रणाली में निहित लॉजिस्टिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और वैश्विक भू राजनीतिक व्यवधानों के विरुद्ध आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5

भारत ने बनाया पहला प्राइवेट 800 kN FFSC रॉकेट इंजन, ग्लोबल क्लब में शामिल

चर्चा में क्यों Astrobase Space Technologies ने भारत के पहले निजी रूप से निर्मित 800 kN FFSC रॉकेट इंजन का अनावरण किया है, जिससे भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है।

विज्ञान	FFSC: Full-Flow Staged Combustion एक उच्च-दक्षता वाला रॉकेट इंजन चक्र है।
तथ्य	भारत FFSC तकनीक रखने वाला चौथा देश है, जिसमें वह रूस, USA और China के साथ शामिल हो गया है।
विज्ञान	EVEREST इंजन में प्रणोदक (propellants) के रूप में LOX (Liquid Oxygen) और Methane का उपयोग किया जाता है।
स्थान	Astrobase Space Technologies का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।

मेन्स प्रश्न भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व और उच्च-स्तरीय एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

भारत की डिफेंस कमेटी ने मांगा Sixth-Generation फाइटर एयरक्राफ्ट का रोडमैप

चर्चा में क्यों रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत की तकनीकी बढ़त सुनिश्चित करने के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय (MoD) से एक रूपरेखा (roadmap) की मांग की है।

संस्था	रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति: रक्षा व्यय और नीतियों की निगरानी के लिए लोकसभा/राज्यसभा की एक समिति।
तथ्य	छठी पीढ़ी के विमान: उन्नत AI, स्टील्थ और मल्टी-डोमेन क्षमताओं से लैस अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान।
पद	रक्षा मंत्रालय (MoD): देश की रक्षा क्षमताओं और खरीद के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।

मेन्स प्रश्न रक्षा क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और तकनीकी नेतृत्व सुनिश्चित करने में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।

बाढ़ प्रभावित असम में 100 वाटर प्यूरीफायर मिले, बिना बिजली के हर घंटे 2,500 लीटर पानी उत्पादन

चर्चा में क्यों CSIR-NEERI के वैज्ञानिकों ने बाढ़ प्रभावित असम में बिना बिजली के शुद्ध जल उपलब्ध कराने और प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से 100 NEERI-ZAR जल शोधन इकाइयाँ वितरित करना शुरू किया है।

संस्था	CSIR-NEERI: Council of Scientific and Industrial Research – National Environmental Engineering Research Institute।
विज्ञान	NEERI-ZAR: जल शोधन तकनीक जो बिना बिजली के 2,500 लीटर/घंटा उत्पादन करने में सक्षम है।
तथ्य	पूर्वी असम में वितरित 100 इकाइयाँ (25 सामुदायिक, 75 घरेलू)।

मेन्स प्रश्न जलवायु-प्रेरित आपदाओं के दौरान जल-जनित रोगों और प्लास्टिक प्रदूषण की दोहरी चुनौतियों को कम करने में स्वदेशी तकनीकी नवाचारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Meta ने भारत को दिया Deepfakes और Child Abuse कंटेंट से निपटने का भरोसा

चर्चा में क्यों | भारत सरकार ने Meta के साथ अनुपालन वार्ता आयोजित की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी अनुशंसा प्रणाली (recommendation systems) और सामग्री संवर्धन (content promotion) डीपफेक्स (deepfakes) और बाल शोषण सामग्री के संबंध में IT Act के अनुरूप हों।

विज्ञान	Deepfakes: सिंथेटिक मीडिया जिसमें किसी मौजूदा छवि या वीडियो में एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप के साथ बदल दिया जाता है।
अधिनियम	Information Technology (IT) Act: भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून।
तथ्य	Meta की 'intermediary' के रूप में स्थिति इसे अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई थर्ड-पार्टी सामग्री के संबंध में विशिष्ट उत्तरदायित्वों (liabilities) के अधीन करती है।

मेन्स प्रश्न | डिजिटल युग में सिंथेटिक मीडिया और डीपफेक द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण और सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए मजबूत विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

केरल के AI Farmguard ने जंगली जानवरों को भगाने में हासिल की लगभग 100% सफलता

चर्चा में क्यों | केरल ने उच्च-जोखिम वाले वन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 'Farmguard' नामक एक AI-आधारित ध्वनिक रक्षा प्रणाली (acoustic defense system) को सफलतापूर्वक तैनात किया है।

विज्ञान	Farmguard: मल्टी-फ्रीक्वेंसी एकोस्टिक डिफेंस का उपयोग करने वाला एक AI-संचालित डिजिटल सेंट्री सिस्टम।
तथ्य	यह प्रणाली वन्यजीवों को दूर रखने के लिए 100 से अधिक विभिन्न ऑडियो पैटर्न का उपयोग करती है।
स्थान	पायलट ज़ोन में केरल के मंकला, कोल्लम, त्रिशूर और पलक्कड़ शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न | केरल जैसे जैव विविधता से समृद्ध राज्यों में मानव-वन्यजीव संघर्षों को प्रभावी ढंग से कम करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का एकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

3

Lalbagh को बचाने के लिए बेंगलुरु एक्टिविस्ट्स ने बनाया ₹17,770 करोड़ के टनल रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ ह्यूमन चेन

चर्चा में क्यों | बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने लालबाग बॉटैनिकल गार्डन की पारिस्थितिक अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ₹17,770 करोड़ की टनल रोड परियोजना के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई।

स्थान	लालबाग: बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख वनस्पति उद्यान और विरासत स्थल।
तथ्य	प्रस्तावित टनल रोड परियोजना की अनुमानित लागत ₹17,770 करोड़ है।
तथ्य	लालबाग रॉक को लगभग 3,300 वर्ष पुरानी एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता के रूप में उद्धृत किया गया है।

मेन्स प्रश्न | भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और शहरी हरित क्षेत्रों एवं विरासत स्थलों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।

Bengaluru में GBA ने Plaster of Paris और non-biodegradable गणेश मूर्तियों पर लगाया बैन

चर्चा में क्यों | त्योहार के दौरान जल प्रदूषण को नियंत्रित करने उद्देश्य से, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) और गैर-बायोडिग्रेडेबल गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अधिनियम	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम: भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राथमिक विधान।
तथ्य	प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP): एक सिंथेटिक जिप्सम सामग्री जो गैर-बायोडिग्रेडेबल है और जल प्रदूषण में योगदान देती है।
स्थान	Greater Bengaluru Authority (GBA): बेंगलुरु में पर्यावरणीय नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नागरिक निकाय।

मेन्स प्रश्न | शहरी जल निकायों पर धार्मिक त्योहारों के पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा कीजिए और इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने में विधायी उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

असम में बाढ़ से 98 की मौत, मुख्यमंत्री ने मांगी 'National Solution'

चर्चा में क्यों: बादल फटने और नदी के तट टूटने के कारण असम में आई भीषण बाढ़ में 98 लोगों की मृत्यु हो गई, जो राष्ट्रीय स्तर की आपदा प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

स्थान	डिकहो नदी: असम की एक प्रमुख नदी जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील है।
तथ्य	असम में बाढ़ के कारण वार्षिक रूप से ₹1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
पर्यावरण	क्लाउडबर्स्ट (Cloudbursts): पर्वतीय/पहाड़ी क्षेत्रों में नमी के अचानक संघनन (condensation) के कारण होने वाली तीव्र वर्षा।

मेन्स प्रश्न पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति पर पर्यावरणीय क्षरण और ऊपरी जलधारा (अपस्ट्रीम) की गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए तथा एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

आंतरिक सुरक्षा

5

CDS राजा सुब्रमण्यम ने कमान संभाली, मिलिट्री थिएटर कमांड्स के लिए डेडिकेटेड टीम बनाएगी काम तेज़

चर्चा में क्यों: सरकार ने एक एकीकृत युद्ध-लड़ाकू संरचना बनाने के उद्देश्य से सैन्य थिएटर कमांड्स के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है।

पद	चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): सरकार को सैन्य सलाह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक त्रि-सेवा (tri-service) पद।
संस्था	रक्षा पर स्थायी समिति (Standing Committee on Defence): एक संसदीय समिति जिसे मंत्रालय के व्यय और नीतियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
तथ्य	थिएटर कमांड्स: विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना को एक एकल परिचालन कमान के तहत एकीकृत करने हेतु एक संरचनात्मक बदलाव।

मेन्स प्रश्न समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में भारत की संयुक्त सैन्य क्षमता और एकीकृत युद्ध-कौशल को बढ़ाने में थिएटर कमांड्स के महत्व की चर्चा कीजिए।

आतंकी अलर्ट के बीच J&K पुलिस ने सोपोर में Jamaat-e-Islami की 26 साइट्स पर छापेमारी की

चर्चा में क्यों: क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि के पश्चात, J&K पुलिस ने UAPA के अंतर्गत सोपोर में जमात-ए-इस्लामी की 26 ठिकानों पर छापेमारी की।

अधिनियम	UAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act आतंकवाद से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
तथ्य	Jamaat-e-Islami (Jel) प्रतिबंध विस्तार: फरवरी 2024 में पांच वर्षों के लिए विस्तारित।
संस्था	CRPF: Central Reserve Police Force आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में राज्य पुलिस की सहायता करती है।
स्थान	सोपोर: उत्तर कश्मीर में स्थित, सुरक्षा अभियानों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र।

मेन्स प्रश्न जम्मू और कश्मीर में कट्टरपंथ और आतंकवाद से जुड़े संगठनों को निष्प्रभावी करने में आंतरिक सुरक्षा बलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

मणिपुर सरकार ने एथनिक ब्लॉकडों के बाद हाईवे दोबारा खोलने की घोषणा की

चर्चा में क्यों: मणिपुर सरकार ने लंबे समय से जारी जातीय अवरोधों के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों को पुनः खोलने की घोषणा की है, जो राज्य में निरंतर बनी रहने वाली आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक चुनौतियों को रेखांकित करता है।

स्थान	मणिपुर: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जो जातीय संघर्ष और राजमार्गों की नाकेबंदी का सामना कर रहा है।
तथ्य	मणिपुर में मई 2023 से नाकेबंदी जारी है।
पद	यूमनाम खेमचंद सिंह: मणिपुर के मुख्यमंत्री।

मेन्स प्रश्न पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों और बुनियादी ढाँचे की नाकेबंदी के बीच आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

महाराष्ट्र ने ISIS और Al Qaeda से जुड़े 114 चरमपंथी सामानों पर लगाई रोक

चर्चा में क्यों महाराष्ट्र सरकार ने हिंसक कट्टरपंथ के प्रचार को रोकने और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए ISIS और Al Qaeda से जुड़े 114 चरमपंथी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- संस्था | ATS: महाराष्ट्र में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी State Anti-Terrorism Squad है।
- तथ्य | महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रिकाओं और पुस्तकों सहित 114 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया।
- तथ्य | यह प्रतिबंध ISIS और Al Qaeda से जुड़े साहित्य को लक्षित करता है।

मेन्स प्रश्न भारत में वैश्विक आतंकवादी विचारधाराओं और कट्टरपंथ के प्रभाव का मुकाबला करने में राज्य-स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Independence Day ड्रिल में दिल्ली पुलिस और NSG ने किया ब्लास्ट और हाईजैकिंग का मॉक ड्रिल

चर्चा में क्यों दिल्ली पुलिस और NSG द्वारा स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने हेतु 'सुदर्शन शक्ति-V' नामक एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया गया।

- संस्था | NSG: National Security Guard गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद विरोधी इकाई है।
- संस्था | NDRF: National Disaster Response Force आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल है।
- तथ्य | CBRNE का तात्पर्य Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, और Explosive खतरों से है।
- संस्था | CISF: Central Industrial Security Force मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

मेन्स प्रश्न CBRNE और अपहरण जैसे अपरंपरागत खतरों के विरुद्ध भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में बहु-एजेंसी समन्वय और संयुक्त अभ्यासों के महत्व पर चर्चा कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।